Union Government has urged the States to implement the Powerloom Workers Insurance Scheme.

(b) Six State Governments had started implementing the Powerloom Workers Insurance Scheme during the year 1993-94. The other States are actively considering its adoption.

(c) Under this scheme an annual premium of Rs. 120 for an Insurance cover of Rs. 10,000 is to be equally shared by the Central Government State Government and the Powerloom Worker. Therefore, an assistance of Rs. 40 per worker insured would be provided by the Union Government.

Recovery of Excise and Customs Locked up in Litigation

*409. SHRI RAJNI RANJAN SAHU :
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) how much of recoveries on account of Central Excise and Customs are locked up in litigation for over a year; and

(b) what steps are being taken to speed up the recovery ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) The amounts of Customs and Central Excise duties/penalties, as on 31-12-93, whose recovery has been stayed by the Supreme Court and High Courts are as follows :—

(Amount in Crores)

	Supreme Court	High Court
Central Excise	207.99	805.90
Customs	31.09	15.20

(b) Steps taken to speed up the recovery of revenue locked up in litigation, include periodical review and monitoring of cases pending before various courts, furnishing to courts issue-wise list of pending cases to enable their being bunched for early disposal, filing caveats in some cases in courts to obviate ex-parte stays and close liaison with Ministry of Law for pursuing the Supreme Court and the High Courts for early hearing of cases and vacation of stay orders.

टिहरी बांध परियोजना में परिवर्तन

*410. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टिहरी बांध परियोजना के मूल रूप को बहुत बदल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना पर मूल रूप से कितनी राशि व्यय किए जाने का अनुमान था;

(ग) अब इस परियोजना के निर्माण पर कुल कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है;

(घ) मार्च, 1994 तक इस परियोजना पर कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी है;

(ङ) क्या यह सच है कि सरकार अभी तक परियोजना के निर्माण के लिए अपेक्षित राशि की पूर्ण व्यवस्था नहीं कर पाई है; और

(च) यदि हां, तो परियोजना के शेष निर्माण कार्य के लिए आवश्यक राशि किन-किन स्रोतों से जुटाई जाएगी ?

विद्युत मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) और (ख) : टिहरी बांध परियोजना को मूल रूप में एक राज्य क्षेत्र परियोजना के रूप में 197.92 करोड़ रुपये की लागत पर 600 मे० वा० की प्रतिष्ठापित क्षमता के साथ जून, 1972 में निवेश मंजूरी प्रदान की गई थी। तत्पश्चात्, 1983 में प्रतिष्ठापित क्षमता को 1000 मे० वा० तक बढ़ा दिया गया था। एक वृहत् जल विद्युत काम्प्लैक्स के कार्यान्वयन हेतु सोवियत ऋण की उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए 1986 में अन्य संघटकों की संवृद्धि के साथ इस परियोजना की क्षमता को और बढ़ाकर 2400 मे० वा० कर दिया गया था।

(ग) टिहरी बांध परियोजना (1000 मे० वा०) को अब कार्यान्वयन हेतु, 3334.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किया गया है।

(घ) मार्च, 1994 तक इस परियोजना पर 873 करोड़ रुपये (अनंतिम) की राशि खर्च की जा चुकी है।

(ङ) तथा (च) राज्य सरकार की संसाधन कठिनाइयों के कारण टिहरी परियोजना को भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उपक्रम के रूप में सोवियत तकनीक तथा वित्तीय सहायता के साथ एक वृहत् जल विद्युत काम्प्लैक्स के एक अंग के रूप में कार्यान्वयन हेतु हाथ में लिया गया था। सोवियत संघ का विघटन होने से सोवियत ऋण अब उपलब्ध नहीं है। और इस प्रकार टिहरी परियोजना के लिए संशोधित वित्त पोषण व्यवस्था की गई है।

इस व्यवस्था के अनुसार टिहरी बांध परियोजना का निष्पादन भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुहैया कराई गई निधियों के माध्यम से और अंशतः पूर्तिकारों के ऋण के माध्यम से किया जाएगा ।

Dollar currency purchased by RBI

*411. SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Reserve Bank of India has purchased dollar currency from the open market ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the details of such purchase made by the Reserve Bank of India during 1993-94;

(d) whether Government have taken any measures to stem the flood of dollars in the Indian market; and

(e) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) and (b) Yes, Sir. The Reserve Bank of India has been purchasing US dollar from the Inter-Bank Market. Under Section 40 of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Bank is required to quote its rates for spot purchase and sale of US dollars from/to authorised dealers in India. When the authorised dealers find the Bank's purchase rate attractive compared to the ongoing market rate or when there is no demand for US dollar in the inter-bank market they sell the US dollar currency to the RBI. Also, since the Reserve Bank of India is required to effect debt service payments on behalf of the Government of India and accounts for aid receipts as well, RBI purchases US dollars from the inter-bank market as and when there is a shortfall in aid flows compared to the debt service payments.

(c) The purchases made by the RBI during April, 1993 to March, 1994 amounted to US $ 13,855 million Month-wise details are as follows :—

	US $ (in million)
April 1993	820
May 1993	412
June 1993	619
July 1993	873
August 1993	786
September 1993	660
October 1993	862
November 1993	1007
December 1993	1839
January 1994	1189
February 1994	2929
March 1993	1859
Total	13855

(d) and (e) The strong improvements in the current account of the balance of payments in 1993-94 and the much higher flows of non-debt creating capital in the capital account have helped us build our foreign exchange reserves to comfortable levels.

उपग्रह मनीआर्डर प्रणाली

*412. **श्रीमती वीणा वर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश के कुछ चुनिंदा स्थानों पर, उन स्थानों को उपग्रह से जोड़कर माइक्रो अर्थ-स्टेशनों के माध्यम से मनीआर्डर भेजने की योजना शुरू कर रही है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस योजना की अनुमानित लागत कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि डाक विभाग विद्यमान प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मनीआर्डर को भेजने पर 1.86 रुपये की हानि उठाता है तथा उपग्रह प्रणाली से समय की बचत होगी तथा लागत भी कम आएगी; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) मध्य प्रदेश में ऐसे कितने गांव हैं, जिनमें अब तक डाकघर नहीं हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैय्या नायडू) : (क) मनीआर्डर को एक डाकघर से दूसरे डाकघर को शीघ्र भेजने और साथ ही मनीआर्डर प्रचालन की लागत में कमी लाने के उद्देश्य से विभाग ने 8 वीं योजना अवधि के दौरान देश में 75 स्थानों पर माइक्रो-अर्थ स्टेशन स्थापित करने का एक कार्यक्रम बनाया है । माइक्रो-अर्थ स्टेशन स्थापित करने के लिए 75 स्थानों की सूची विवरण दी गई है (नीचे देखिए)

विभाग ने पांच स्थानों, अर्थात् दिल्ली, मद्रास, बेंगलूर, लखनऊ और शिमला में पहले ही एक प्रायोगिक योजना शुरू कर दी है ।